In addition the blast furnace under erection is being equipped with all the necessary facilities to take care of pollution control norms.

(c) M/s ELKEM METALLURGY PVT. LTD., Bombay, the organisation which has been entrusted the job of modernisation of Ferro Silicon Furnaces, had arranged two Norwegian Experts from M/S. ELKEM TECHNOLOGY, Norway, their principals, to oversee the supervision of the erection of one of the ferro silicon furnaces being modernised. These experts have left after completion of the erection work. VISL have also arranged a Norwegian process metallurgist from M/s. ELKEM TECHNOLOGY, Norway to assist in commissioning the modernised furnace.

(d) and (e) First ferro silicon furnace has been commissioned after modernisation. Once it is stabilised, the job of second Ferro Silicon Furnace will be taken up.

लघु इस्पात-संयंत्रों की स्थापना

2571. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने वाले लघु इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ परियोजनाओं से संबद्ध कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (ग) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट दे दी गई है। लोहा अथवा इस्पात की इकाई लगाने के इच्छुक उद्यमी को औद्योगिक लाइसेंस के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है बशर्ते संयंत्र को 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की मानक शहरी क्षेत्र सीमा के 25 कि.मी. के भीतर स्थापित न किए जाने का प्रस्ताव हो।

सामान्यत: लघु इस्पात संयंत्र का तात्पर्य विद्युत चाप भट्टी प्रक्रिया के माध्यम से तुलनात्मक रूप से कम क्षमता की इस्पात-निर्माण इकाइयों से है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान स्थापित की जा रही 5 लाख टन वार्षिक से कम क्षमता की निम्नलिखित 3 विद्युत चाप भट्टी इकाइयां हैं:

कम्पनी का नाम	स्थान और क्षमता (टन वार्षिक)	उत्पादन शुरू होने की सम्भावित तारीख	परियोजना लागत (लाख रु.)	कार्यान्वयन में प्रगति
राजिन्द्र स्टील लिमिटेड	रायपुर, मध्य प्रदेश (1.7 लाख)	अक्तूबर, 94	17550 (विद्युत चाप भट्टी प्रक्रिया पर आधारित एच.आर.क्वायल परियोजना)	भूमि अधिग्रहीत कर ली गई, स्थल विकास कार्य पूरे हो गए। संयंत्र और मशीनरी के जुलाई 94 तक स्थल पर पहुंचने की संभावना है। वाणिज्यिक उत्पादन अक्तूबर, 1994 में शुरू करने की समय-अनुसूची है।
रेमी मैटल (गुजरात)	बरूच गुजरात(1 लाख)	अगस्त, 94	22000 (विद्युत चापभट्टी प्रक्रिया पर आधारित बैलिस्ट उत्पाद)	भूमि अधिग्रहीत कर ली गई, स्थल विकास कार्य पूरे कर लिए गए। भवन तैयार हो गया। आयातित संयंत्र और मशीन स्थल पर पहुंच गए हैं।
लायड स्टील इण्डस्ट्रीज लि.	वर्धा, महाराष्ट्र (एच.आर.: 4 लाख जी.पी. / जी.सी. / सी.आर.सी.ए.: 2.25 लाख)	अक्तूबर, 94 एच.आर. / सी.आर. मिल 1995 में उत्पादन आरम्भ कर देगी।	88500 (विद्युत चापभट्टी प्रक्रिया पर आधारित चपटे उत्पाद)	एच.आर. परियोजना अक्तूबर, 94 तक चालू होगी। (चाप भट्टी मई, 94 में शुरू हो गई है) सी.आर. परियोजना का सिविल कार्य चल रहा है।

दिल्ली में रिजों पर अधिक्रमण

2572. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में रिजों की संख्या कितनी है;

(ख) इन रिजों के अधीन कुल कितना क्षेत्र है;

(ग) उक्त क्षेत्र में से कितने क्षेत्र का अधिक्रमण किया गया है;

(घ) कितने क्षेत्र पर वैध कब्जा है; और

(ङ) क्या सरकार पर्यावरण की दृष्टि से इन रिजों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में भूमि के वैध और अवैध कब्जों को हटाने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) दिल्ली में चार रिज हैं, अर्थात (i) उत्तरी रिज, (ii) सेन्ट्रल रिज, (iii) दक्षिण-सेन्ट्रल रिज और (iv) दक्षिण-रिज

(ख) 7,777 हैक्टेयर।

(ग) श्री लवराज कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने बताया है कि 39 अतिक्रमणों की पहचान की गई है जिनमें धार्मिक स्थान, विद्यालय, मोटर वर्कशाप, दुकानें, गोदाम, आदि शामिल हैं। अतिक्रमणाधीन वास्तविक क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) उक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 80 "आबंटनों" की पहचान की गई है जिनमें कई पेट्रोल पम्प-सर्विस स्टेशन, मिलिट्री क्षेत्र, जलाशय, कुछ विद्यालय, धार्मिक स्थान, एक योगाश्रम, इसरो का अर्थ स्टेशन, पुलिस वायरलैस स्टेशन आदि शामिल है। इन आबंटनों द्वारा कवर्ड/ वास्तविक क्षेत्र ज्ञात नहीं है।

(ङ) हरित रिज के क्षेत्र में और कमी को रोकने के लिए, सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया गया है कि रिज क्षेत्र में किसी भी संस्थान को कोई और आबंटन न किया जाए तथा रिज क्षेत्र में किसी अनधिकृत अतिक्रमण को भी नियमित नहीं किया जाए।

Use of partition terrace by Cooperative Group Housing Societies

2573. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether DDA has permitted the first and second floor allottees of some Cooperative Group Housing Societies to make use of the partitioned terrace floor;

(b) if so, names of such societies with background for such a move;

(c) whether Government propose to extend similar facilities to allottees of other Cooperative Group Housing Societies also;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(e) whether Government also propose to extend the same facilities to first and second floor allottees of DDA flats; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (b) DDA has reported that building plans providing partitioned spaces on the terraces up to 3 feet high have been permitted only in the case of Gujrawala Co-operative Group Housing Society, which had only 3 floors. Since their proposal was not objectionable, the permission was given.

(c) and (d) Proposals, from Societies for utilisation of terrace spaces which do not cause inconvenience to individual members and are other-wise not objectionable from Building Bye-laws point of view, are examined on merit of each case.

(e) and (f) No, sir. In DDA flats, the terrace is meant for the use of top floor allottees only. However, the allottees of other floors can put their water tank and T.V. antenna on the terrace.

Development of Trans-Yamuna area by DDA

2574. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether DDA has drawn up any scheme/ project for the development of the Trans-Yamuna areas;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how much money has been set apart for the scheme/project and by when the scheme/ project will be started?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) DDA has prepared draft zonal plan for Trans-Yamuna area which includes development and construction of hospitals, poly-clinics, nursing homes, dispensaries, schools of all levels, colleges, post and telegraph